भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2940

दिनांक 13.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत की शून्य–आतंकवाद कूटनीति पर प्रतिक्रिया

2940 श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात भारत की शून्य–आतंकवाद सहनशीलता नीति का प्रचार करने हेतु 33 देशों की यात्रा करने वाले सात संसदीय प्रतिनिधिमंडलों को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल और जापान सहित प्रमुख राजधानियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) विदेशी वार्ताकारों द्वारा उल्लिखित सुरक्षा साझेदार, आतंकवाद–निरोधी सहयोग अथवा एफएटीएफ समन्वय जैसे सक्रिय सहयोग के अनुमोदित क्षेत्र कौन–से हैं; और

(ग) इस विदेशी प्रतिक्रिया को भारत की आतंकवाद–निरोधी भावी कूटनीति और बहुपक्षीय पक्ष–समर्थन में संकलित, विश्लेषित और एकीकृत करने हेतु मंत्रालय ने क्या उपाय किए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) 'ऑपरेशन सिन्दूर' के पश्चात सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने 33 देशों की यात्रा की और आतंकवाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों से निपटने के संबंध में भारत की सुदृढ़ राष्ट्रीय सहमति तथा दृढ़ दृष्टिकोण को व्यक्त किया। मेजबान देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और सीमा पार आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए भारत की लड़ाई में अपनी एकजुटता व्यक्त की। आतंकवाद के प्रति भारत के 'शून्य सहिष्णुता' के दृष्टिकोण के अनुरूप, यह पुनः स्पष्ट किया गया

कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता। मेजबान देशों को पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के न्यू नॉर्मल दृष्टिकोण के बारे में भी अवगत कराया गया। माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की वापसी पर उनसे मुलाकात की और उनके अनुभवों तथा सुझावों का संज्ञान लिया।

मेज़बान सरकारों ने आतंकवाद से निपटने से संबंधित सभी मामलों, जिनमें आतंकवादियों को प्रतिबंधित करना और आतंकवाद–वित्तपोषण के चैनलों को अवरुद्ध करना शामिल है, पर भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई 2025 को आतंकवादी समूह "द रेजिस्टेंस फ्रंट" को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठन (एफ.टी.ओ.) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एस.डी.जी.टी.) के रूप में नामित किया गया था। इसी प्रकार, 24 जुलाई 2025 की 36वीं यू.एन.एस.सी. 1267 प्रतिबंध समिति निगरानी रिपोर्ट में पहलगाम आतंकवादी हमले से टी.आर.एफ. के संबंधों का उल्लेख किया गया था।

पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों के साथ–साथ बहुपक्षीय मंचों के परिणाम दस्तावेजों में भी परिलक्षित हुई, जिनमें 25 अप्रैल 2025 का यू.एन.एस.सी. प्रेस वक्तव्य, 06 जून 2025 को चौथा भारत–मध्य एशिया विदेश मंत्रियों का संवाद, 16 जून 2025 का एफ.ए.टी.एफ. सार्वजनिक दस्तावेज, 01 जुलाई 2025 को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का संयुक्त वक्तव्य और 06 जुलाई 2025 का ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन का घोषणापत्र शामिल हैं।

भारत आतंकवाद–रोधी सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ निरंतर सहभागिता बनाए हुए है। यह सहभागिता 31 देशों (जिनमें इन 33 देशों में से कुछ शामिल हैं) और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ स्थापित 'आतंकवाद–रोधी संयुक्त कार्य समूहों' जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से संचालित की जा रही है।

*****